



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 29 सितम्बर, 1995/7 आश्विन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 सितम्बर, 1995

संख्या 1-45/95-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कुड़ा-रुचरा (नियन्त्रण) विधेयक (1995 का

विधेयक संख्यांक 10) जो कि दिनांक 28 सितम्बर, 1995 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव

1995 का विधेयक संख्यांक 10.

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) विधेयक, 1995

!(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में मार्बजनिक नालियों, सड़कों और जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थानों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकने या जमा करने को निवारित करने और उससे सम्बन्धित या आनुवंशिक विषयों के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 है ।

संक्षिप्त
नाम, विस्-
तार और
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) “जीव नाशित कूड़ा-कचरा” से जीवित प्राणियों की क्रिया द्वारा नाशित किए जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है;

(ख) “सफाई गली” से रास्ता या भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है जो नाली के रूप में प्रयुक्त किए जाने या नाली निकालने के लिए अथवा शौचालय, मूत्रालय, मलकुंड तक या गन्दगी या अन्य दूषित पदार्थ के लिए अन्य पात्र तक, उसकी सफाई के लिए या उसमें से ऐसे पदार्थ को हटाने के लिए नियोजित व्यक्तियों के आने-जाने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है, पृथक रखा गया है या प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) “स्थानीय प्राधिकरण” से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या जारी रखा गया नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, छावनी, बोर्ड जिला परिषद्, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(घ) “मंडी” के अन्तर्गत, इस बात के होते हुए भी कि क्रेताओं और विक्रेताओं के जमा के लिए कोई सामान्य विनियम नहीं है और स्थान के स्वामी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा मंडी के कारबार या मंडी में बर-बार आने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखा जाता है, या नहीं, कोई ऐसा स्थान है, जहां ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मति सहित या रहित, व्यक्ति, मानव प्रयोग अथवा उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जियां, भोजन या अन्य वस्तुएं विक्रय के लिए, रखने के लिए, एकत्र होते हैं;

(ड) "जीव अनाशित कूड़ा-कचरा" से ऐसा कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है जो जीव-नाशित नहीं है और इसके अन्तर्गत पोलिथीन, नाईलोन और प्लास्टिक का अन्य मान जैमे पी0वी0सी0, पालीप्रोप्लीन और पालिस्टाइरीन जो जीवित प्राणियों की क्रिया द्वारा नाशित किए जाने योग्य नहीं है और जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट गम्मिलित है;

(च) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

- (क) कोई व्यक्ति जो स्वामी को तत्समय उस भूमि या भवन के भाटक या भाटक का कोई भाग संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का जिम्मेदार है, जिसकी बाबत ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या देय है;
- (ख) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा उसका प्रयोग करता है;
- (ग) किसी भूमि या भवन का भाटकमुक्त अभिधारी;
- (घ) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग और अधिभोग के लिए उसके स्वामी को नुकसानी संदत्त करने का दायी है;
- (छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्यो के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को पट्टे पर दे दिया जाए तो इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा, या प्राप्त करने का हकदार होगा;
- (ज) "स्थान" से कोई भूमि या भवन अथवा भवन का भाग अभिप्रेत है और किसी भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन और उपगृह, यदि कोई हो, इसके अन्तर्गत है;
- (झ) "जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राइवेट स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा है जो किसी सार्वजनिक स्थान में, या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई देता हो;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "लोक विष्णेषक" से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी पर्यावरणिक प्रयोग-शाला के सम्बन्ध में सरकारी विष्णेषक के रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और
- (ठ) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो सर्वसाधारण के प्रयोग और उपयोग के लिए खुला है चाहे उसका सर्वसाधारण द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग किया जाता है या नहीं और सड़क, मार्ग, मण्डी, सफाई रास्ता या रास्ता, चाहे वह आम रास्ता है या नहीं या उतरने का स्थान जहां सर्वसाधारण की पहुंच है या आने-जाने का अधिकार है अथवा जिस पर उन्हें जाने का अधिकार है, इसके अन्तर्गत है।

3. कोई भी व्यक्ति, स्वयं या अन्य के माध्यम से जानबूझकर या अन्यथा—

सार्वजनिक स्थानों, नालियों और मल-नालियों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकेगा या फैकवाएगा, जिससे,—

(1) किसी प्राइवेट या सार्वजनिक जल निकास संकमी में सम्बन्धित किसी नाली, संवानन नाल, पाइप और फिटिंगों में कोई जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित थैले या पात्र में कोई जीव-नाशित कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेगा या फैकवाएगा, जिससे,—

(i) जल निकास और मल व्ययन प्रणाली को क्षति पहुंचने; या

(ii) निर्बाध प्रवाह में बाधा पड़ने या अन्तर्वेम्न की अभिक्रिया और व्ययन पर प्रभाव पड़ने; या

(iii) जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या न्यूसैन्स का कारण अथवा प्रति-कूल प्रभाव पड़ने; की सम्भावना है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जानबूझकर या अन्यथा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपाय का जो विहित किया जाए, पालन करने के पश्चात् के सिवाय किसी जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़े-कचरे को, किसी सार्वजनिक स्थान या जनता को दृष्टिगोचर स्थान में नहीं रखेगा या रखने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि—

(क) कूड़ा-कचरा किसी कूड़ा-कचरा पात्र में नहीं रखा जाता है, या

(ख) किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कूड़े-कचरे के व्ययन के लिए अभिविहित स्थान में कूड़ा-कचरा जमा नहीं किया जाता है।

4. स्थानीय प्राधिकरण या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए कूड़ा-दान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना।

(क) जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी तौर पर जमा या संग्रहण के लिए उचित और सुविधाजनक स्थिति में सार्वजनिक कूड़ेदान रखना या संग्रह स्थानों या जगह की व्यवस्था करना ;

(ख) जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने के लिए, जीव नाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए रखी गई और अनुपक्षित से भिन्न, अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करना ;

(ग) कूड़ादानों, कूड़ास्थानों की अन्तर्वेम्न और डम धारा के खण्ड (क) के अधीन डम द्वारा व्यवस्थित या नियत सभी स्थानों के ढेर को हटाने की व्यवस्था करना ;

(घ) डम अधिनियम के अधीन संगृहीत जीव अनाशित कूड़े-कचरे के पुनः चक्रण का प्रबन्ध करना।

जीव अना- 5. सब भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों का निम्नलिखित कर्तव्य
शित कूड़ा- होगा -
कचरा आदि

संगृहीत और
जमा करने
का स्वामियों
और अधि-
भोगियों का
कर्तव्य ।

(क) अपनी-अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा-कचरा संगृहीत करना या करवाना और सार्वजनिक कूड़ादानों, संग्रह स्थानों या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने या संगृहीत करने के लिए व्यवस्थित स्थानों में जमा करना या करवाना ;

(ख) जीव नाशित कूड़े-कचरे को जमा करने के लिए रखी गई और अनु-रक्षित से भिन्न, ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़े-कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकरण या इसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों/कचरा-पेटियों को अच्छी दशा और अवस्था में रखना ।

जीव अना-
शित कूड़ा-
कचरा हटाने
की स्थानीय
प्राधिकरण
की शक्ति ।

6. स्थानीय प्राधिकरण, लिखित नोटिस द्वारा, किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े-कचरे का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया है, और न्यूसैन्स का कारण बनने की सम्भावना है, स्वामी या अधिभोगी अथवा भागिक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाए गए या संग्रहीत उक्त कूड़े-कचरे को हटाने या हटवाने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, इसकी राय में, जीव अनाशित कूड़े-कचरे के ऐसे ढेर या संग्रहण से जल निकास और मल व्ययन प्रणाली को क्षति होने या जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना है, तो यह तुरन्त ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे पग उठाएगा जो यह आवश्यक समझे ।

अध्ययन,
अनुसंधान
और समर्थन
कार्यक्रम ।

7. राज्य सरकार —

(क) जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़े-कचरे के सम्मिश्रण के अवधारण के लिए अध्ययन का जिम्मा ले सकेगी ;

(ख) अपशिष्ट के स्रोत में कमी या इसके पुनःप्रयोग और पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान या कार्यक्रमों के संचालन या बढ़ावा देने के उपाय नियत कर सकेगी ;

(ग) घरेलू और अन्य ठोस अपशिष्ट पृथक-करण स्कीमों की सामाजिक और आर्थिक साधयता अवधारित करने के लिए अध्ययनों का संचालन कर सकेगी और बढ़ावा दे सकेगी, जिसके अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों में पुनः चक्रण योग्य पदार्थों के प्रकार और मात्रा है ;

(घ) राज्य में, निवासियों के लिए, जिनके कूड़ा-कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था नहीं है, सुगमता से पहुंचने वाले ठोस अपशिष्ट संग्रहण स्थानों की व्यवस्था करने के लिए, स्थानीय प्राधिकरणों को प्रोत्साहित कर सकेगी ;

- (ङ) अपशिष्ट पदार्थों के पुनः चक्रण की नीतियों के कार्यान्वयन ऊर्जा संरक्षण की अभिवृद्धि करने और पुनः चक्रीय पदार्थों से बने उत्पादों को खरीदने का जिम्मा ले सकेगी और स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकेगी ;
- (च) पुनः चक्रण पर अनुसंधान जिसके अन्तर्गत संचालन पुनः चक्रण कारखाने पर सूचना और पुनः चक्रणीयों पर मंडी सूचना भी है का संचालन कर सकेगी और बढ़ावा दे सकेगी ;
- (छ) सर्वसाधारण, स्थानीय प्राधिकरण, संस्था और उद्योगों के शिक्षण के प्रयोग के लिए अपशिष्ट प्रबन्ध और पुनःचक्रण पर अनुसंधान का संचालन कर सकेगी/बढ़ावा दे सकेगी ;
- (ज) विनिर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या व्यापार करते हैं पर, किस्म, आकार, पैकेजिंग, लेबल लगाना और पैकेजिंग की संरचना की बाबत जो प्रयोग की जा सकती है या की जानी है और पैकेजिंग के व्ययन की वास्तविकता जिसके अन्तर्गत पदार्थों की निम्नीकरणीयता और पुनः चक्रणीयता भी है, अपेक्षाएं अधिरोपित कर सकेगी ।

8. (1) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई अधिसूचना अथवा दिए गए आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य या साक्ष्य लोप का दोषी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। शास्तिमां ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध पाया गया है वह पश्चात्कथित अपराध के लिए उपबन्धित से दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति में अपराध करने में सहायता, दुष्प्रेरण करता है या उपसाधक है, वह दोषसिद्धि पर अपराध के लिए विहित कारावास से दण्डित किया जाएगा ।

9. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारखाने के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा : कम्पनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि

वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी घोर उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और
(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संक्षेपतः विचारण। 10. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे विचारण को लागू होंगे। 1974 का 2

अपराधों का शमन। 11. (1) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐ. अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के खाते में जमा करने के लिए, ऐसी राशि के संदाय पर जो ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, वहां यथा शमनित अपराध के बारे में अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्नोचित कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा निदेश। 12. स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इसे जारी किए जाएं।

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति। 13. जब कभी ऐसा करना समीचीन हो राज्य सरकार, लोकहित में और लोक विश्लेषक के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी जीव अनाशित कूड़े-कचरे की किसी मद को जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति। 14. राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति का (जिसके अन्तर्गत धारा 17 के अधीन नियम बनाने की शक्ति नहीं है) ऐसे मामलों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. इस अधिनियम या अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

16. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके अन्वीकरण में नहीं हैं।

अन्य विधियों का प्रभावित न होना।

17. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों की कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए और तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

[धारा 2 (ङ) देखें]

जीव अनाशित कूड़ा-कचरा :

1. पोलिथिलीन।
2. नाइलोन।
3. पी0बी0सी0।
4. पोलि-प्रोपाईलीन।
5. पोलि-स्टाइरीन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पोलीथिलीन और अन्य प्लास्टिक जैसे कि पी0 बी0 सी0, पोलीप्रोपइलीन और पोली-स्टाइरीन जीव अनाशित प्रकृति के हैं। पोलीथिलीन के थैलों/पोलीथिलीन के पाऊंचों की विद्यमानता से पौधों, सूक्ष्म जीवों और असंख्य वानस्पतिक जातियों की वृद्धि लगभग असम्भव हो जाती है। वर्षा का जल अवमृदा में नहीं रिस सकता है और हानिप्रद रसायनों के विक्षालन से (विशिष्टतः निम्न कोटि प्लास्टिक में) अवमृदा तत्त्वों में अवांछित संदूषण हो गया है। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकास की अनुपस्थिति काटी छोटी होती है और पोलीथिलीन के कारण जल निकास और मल व्ययन प्रणाली के बन्द होने से भारी नुकसान हो सकता है और इससे न्यूसैन्स कारित होने या जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। देश के अन्य भागों में पुनःचक्रण को इस संकट के हल के लिए महत्वपूर्ण समझा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हर रोज तैयार होने वाले कूड़े-कचरे का पर्याप्त भाग पहाड़ियों की खड़ी ढाल से नीचे फँका जाता है और ऐसा कोई ढंग नहीं है जिससे इस कूड़े-कचरे को चिथड़े उठाने वाले पुनः चक्रण के लिए संगृहीत कर सकें। इसलिए पोलीथिलीन वस्तुओं के लौट जा निकास और मल व्ययन नालियों में फँकने या जमा करने को प्रतिबिद्ध करना और उक्त पोलीथिलीन के कूड़े-कचरे या अपशिष्ट सामग्री के पुनःचक्रण के लिए संग्रहण को सुकर बनाना, आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

चन्द्र कुमार,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
सितम्बर 23, 1995.

वित्तीय जापन

प्रस्तावित विधेयक के उपबन्ध विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इसलिए प्रस्तावित उपबन्धों के कार्यान्वयन पर राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत होने की सम्भावना नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक का खण्ड 17 प्रस्तावित विधान के उपबन्धों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। विरचित नियम राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 1995

**THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE
GARBAGE (CONTROL) BILL, 1995**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**A
BILL**

to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage in public drains, roads and places open to public view in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

Definitions.

- (a) “bio-degradable garbage” means the garbage or waste material capable of being destroyed by the action of living beings;
- (b) “house gully” means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as or carrying a drain or affording access to the latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or other polluted matter, by persons employed in the clearing thereof or in the removal of such matter therefrom;
- (c) “local authority” means a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Nagar Panchayat, a Cantonment Board, a Zila Parishad, a Panchayat Samiti or a Gram Panchayat constituted, or continued, under any law for the time being in force;
- (d) “market” includes any place where persons assemble of exposing for sale, meat, fish, fruits, vegetables, food, or any other articles for human use or consumption with or without the consent of the owner of such place, notwithstanding that there may be no common regulation for the concourse of the buyers and the sellers and whether or not any control is exercised over the business of, or the person frequenting, the market by the owner of the place or by any other persons;
- (e) “non-biodegradable garbage” means the waste garbage or material which is not bio-degradable garbage and includes polythylene, nylon, and other plastic goods such as P.V.C., Polypropylene and polystyrene, which are not capable of being destroyed by an action of living beings and are more specifically included in the Schedule to this Act;

(f) "occupier" includes—

- (a) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;
- (b) an owner in occupation of or otherwise using his land or building;
- (c) a rent free tenant of any land or building; and
- (d) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;
- (g) "owner" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant;
- (h) "place" means any land or building or part of a building and includes the garden, ground and out-houses, if any, pertaining to a building or part of a building;
- (i) "place open to public view" includes any private place or building, monument, fence or balcony visible to a person being in, or passing along, any public place;
- (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (k) "Public Analyst" means the person appointed or recognised to be the Government Analysts, in relation to any environmental laboratory established or recognised in the State, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986;
- (l) "public place" means any place which is open to use and enjoyment of the public whether it is actually used or enjoyed by the public or not and includes a road, street, market, house-gully or way, whether a thoroughfare or not, and landing place to which public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass.

29 of 19

Prohibition to throw non-bio-degradable garbage in public drains and sewage.

3. (1) No person, by himself or through another, shall, knowingly or otherwise throw or cause to be thrown in any drain, ventilation shaft, pipe and fittings, connected with the private or public drainage works, any non-biodegradable garbage or any bio-degradable garbage in a non-biodegradable bag or container likely to—

- (i) injure the drainage and sewage system;
- (ii) interfere with the free flow or affect the treatment and disposal of drain and sewage contents; and
- (iii) be dangerous or cause a nuisance or be prejudicial to public health.

(2) No person shall, knowingly or otherwise, place or permit to be placed, except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed, any bio-degradable or non-

biodegradable garbage in any public place or in a place open to public view, unless—

- (a) the garbage is placed in a garbage receptacle; or
- (b) the garbage is deposited in a location designated, by a local authority having jurisdiction on an area for the disposal of the garbage.

4. It shall be the duty of the local authority, or any officer authorised by it, to—

- (a) place or provide or place in proper and convenient situation public receptacles, depots or places for temporary deposit or collection of non-biodegradable garbage;
- (b) provide separate dustbins for temporary deposit of non-biodegradable garbage other than those kept and maintained for deposit of biodegradable garbage;
- (c) provide for the removal of contents of receptacles, deposit and of the accumulation at all places provided or appointed by it under clause (a) of this section; and
- (d) arrange for recycling of the non-biodegradable garbage collected under this Act.

Provision for placement of receptacles and places for deposit of non-biodegradable garbage.

5. It shall be the duty of the owners and occupiers of all lands and buildings—

- (a) to collect or to cause to be collected from their respective land and buildings the non-biodegradable garbage and to deposit, or cause to be deposited, in public receptacles, deposits or places provided for temporary deposit or collection of the non-biodegradable garbage by the local authority in the area;
- (b) to provide separate receptacles or dustbins, other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage, of the type and in the manner prescribed by the local authority or its officers for collection therein of all the non-biodegradable waste from such land and building and to keep such receptacles dustbins in good condition and repair.

Duty of owners and occupiers to collect and deposit non-biodegradable garbage etc.

6. The local authority may, by notice in writing, require the owner or occupier or part-owner, or person claiming to be the owner or part owner of any land or building, which has become a place of unauthorised stacking or deposit of non-biodegradable garbage and is likely to occasion a nuisance, remove or cause to be removed the said garbage so stacked or collected; and if, in its opinion, such stacking or collection of non-biodegradable waste is likely to injure the drainage and sewage system or is likely to be dangerous to life and health, it shall forthwith take such steps at the cost of such persons as it may think necessary.

Power of local authority for removal of non-biodegradable garbage.

Studies,
research and
support pro-
gramme.

7. The State Government may—

- (a) undertake studies to determine the composition of bio-degradable or non-biodegradable garbage;
- (b) establish measures to conduct or support research or programmes to encourage source reduction, re-use and recycling of waste;
- (c) conduct or support studies to determine the social and economic feasibility of household and other solid waste separation schemes, including studies of the type and amount of recyclable materials in solid wastes;
- (d) encourage local authorities in the State to provide readily accessible solid waste collection depots for residents who are not provided with regular garbage pick up;
- (e) undertake and encourage, local authorities and other persons to implement policies to recycle waste materials, to promote energy conservation and to purchase products made from recyclable materials;
- (f) conduct and support research on recycling including information on operating recycling business and market information on recyclables;
- (g) conduct or support research on waste management and recycling, for use in educating the public, local authorities, institutions and industry; and
- (h) impose requirements on manufacturers, distributors and other persons who produce or handle commodities with respect to the type, size, packaging, labelling and composition of packaging that may or must be used and with respect to the disposal of packaging including standards for material degradability and recyclability.

Penalties.

8. (1) Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provision of this Act, or of any rules, notification or order made, issued or given under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with the fine may extend to Rs. five thousand or with both.

(2) Whoever having been convicted of an offence under this Act is again convicted of any offence under this Act shall be punishable with double the penalty provided for the latter offence.

(3) Whoever in any manner aids, abets or is accessory to the commission of an offence under this Act shall on conviction be punished with the imprisonment prescribed for the offence.

Offences by
companies.

9. (1) If the person committing any offence punishable under this Act is a company, every person who, at the time of the commission of the offence, was in charge of, and responsible to the Company for the conduct of the business of the Company, as well as the Company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the

offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any gross negligence on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section—

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

2 of 1974

10. All offences under the Act shall be tried in a summary way by a Judicial Magistrate of the First Class and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply to such trials.

Offences to be tried summarily.

11. (1) Any offence punishable under this Act may, before the institution of the prosecution, be compounded by such officer as may be authorised by the State Government in this behalf, on payment, for credit to the State Government, of such sum as such officer may specify.

Compounding of offences.

(2) Where any offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding shall be taken against the offender, in respect of the offence as compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged.

12. The local authority shall carry out such directions as may be issued to it, from time to time, by the State Government for the efficient administration of this Act.

Directions by the State Government.

13. (1) Where it is expedient to do so, the State Government may, in the public interest and in consultation with the Public Analyst, by notification in the Official Gazette, add to, or omit from the Schedule any item of non-degradable waste and thereafter the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

Power to amend Schedule.

(2) Every notification under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

14. The State Government may, by order published in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act (not including the power to make rules under section 17) may also be exercised, in such cases as may be specified in the order, by such officer or authority, as may be specified therein.

Power to delegate.

15. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the local authority or any officer or other employees of the State Government or of the local authority or any other person authorised by the State Government, for any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

Other laws
not affected.

16. The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to
make rules.

17. (1) The State Government may subject to the condition of previous publication, make rules for the purposes of carrying out of the provisions of this Act.

(2) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid as soon as may be, after it is made before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fourteen days which may comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the sessions in which it is so laid or the successive sessions aforesaid the Assembly agrees, in making any modification in the rule or decides that the rule should not be made the rule shall thereafter have the effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SCHEDULE

[See section 2 (v)]

NON-BIODEGRADABLE GARBAGE

1. Polythylene
2. Nylon
3. P. V. C.
4. Poly-propylene
5. Poly-styrene.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

Polythylene and other plastics such as P.V.C. polypropylene and poly-styrene are non-biodegradable in nature. The presence of the polythylene bags/polythylene pouches makes the growth of plants, micro-organisms and numerous botanical species nearly impossible. The rain water can not percolate to the sub-soil and leaching of harmful chemicals (particularly in low grade plastics) have led to unwarranted contamination of sub-soil elements. Besides this, drainage system in hilly areas has relatively smaller cross section and any choking of drainage and sewage system due to the polythylene can lead to colossal damage, and is likely to cause a nuisance or be prejudicial to public health. In other parts of the country re-cycling has been considered as a solution to this menace. In hilly areas a large fraction of garbage generated every day is thrown down the steep inclines of the hill-sides and there is no way in which this garbage can be collected by rag pickers for re-cycling. Thus it has become necessary to prohibit throwing or deposit of polythylene articles in the public drainage and sewage, and to facilitate the collection of said garbage or waste polythylene material for re-cycling.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

CHANDER KUMAR,
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The 28th September, 1995.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the proposed Bill are to be enforced through the existing Government machinery and hence for the implementation of the proposed provisions no additional expenditure out of the State Exchequer is likely to be incurred.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 17 of the Bill empowers the State Government to make rules for the purpose of carrying out the provisions of the proposed legislation. The rules so framed are to be laid before the State Legislative Assembly. This delegation is essential and normal in character.

